प्रेरणा
“जब तक थक न जाओ, तब तक मत रुको—और जब थक जाओ, तब रुकना मत।”

सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-7 • 19 DECEMBER TO 25 DECEMBER 2025 • VOLUME 22 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

साप्ताहिक मौसम

दिन	अधिकतम	न्यूनतम
शुक्रवार	22°	8°
शनिवार	23°	10°
रविवार	22°	12°
सोमवार	27°	10°
मंगलवार	25°	8°
बुधवार	24°	8°
वीरवार	23°	7°

*आंकड़े आईएमडी के अनुसार

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE CONSULTING | DESIGN | TRAINING
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY
CONFUSED ABOUT CAREER!
Unsure of what to do after 10th/12th/Graduation?
Whether to Study in India or Abroad?
What should I do after 10th-Science, Commerce or Arts?
Should I consider Computer or Mechanical Engineering?
What is better for me - MBA in Marketing or MBA in Finance?
Should I pursue Chartered Accountancy or Law after 12th?
Do I have the aptitude for Architecture and Designing?
Get Career Guidance from our Expert Career Counseling Team Free of Cost
E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9317776662, 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.
*T&C apply

भारत-ओमान ने एफटीए पर किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली. भारत और ओमान ने एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। गुरुवार को हस्ताक्षरित यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। इस समझौते के तहत, ओमान भारत के 98 प्रतिशत से अधिक निर्यात पर शुल्क समाप्त करेगा, जिसमें वस्त्र, कृषि उत्पाद और चमड़े के सामान शामिल हैं। वहीं, भारत ने खजूर, संगमरमर और पेट्रोकेमिकल्स सहित ओमान के आवश्यक उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने पर सहमति जताई है। मस्कट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित यह समझौता अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में प्रभावी होने की उम्मीद है। इस समझौते पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के वाणिज्य, उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब भारत को अपने सबसे बड़े निर्यात गंतव्य, संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 प्रतिशत तक के भारी शुल्क का सामना करना पड़ रहा है।

ओमान का वैश्विक सेवा आयात 12.52 अरब अमेरिकी डॉलर रहा जिसमें भारत की हिस्सेदारी केवल 5.31 प्रतिशत थी। यह भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए अपार संभावनाओं को दर्शाता है। इसके अलावा, सीईपीए की एक प्रमुख विशेषता भारतीय पेशेवरों के लिए आवाजाही की बेहतर रूपरेखा है। ओमान ने पहली बार कुशल पेशेवरों की आवाजाही (मोड-4) के तहत व्यापक प्रतिबद्धताएं पेश की हैं, जिनमें कंपनी के भीतर स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों की सीमा को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। संविदा आधार पर सेवा प्रदान करने वालों के लिए ठहरने की स्वीकृत अवधि में भी वृद्धि की गई है। इसे मौजूदा 90 दिन से बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया गया है। इसे दो वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। यह समझौता लेखांकन, कराधान, वास्तुकला, चिकित्सा और संबद्ध सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों के लिए अधिक उदार प्रवेश एवं ठहरने की शर्तों का प्रावधान भी करता है जिससे गहन तथा अधिक सुगम व्यावसायिक जुड़ाव को बढ़ावा मिलता है। इस समझौते में ओमान के प्रमुख सेवा क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों द्वारा 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रावधान भी है। इसके तहत वाणिज्यिक उपस्थिति के माध्यम से भारत के सेवा उद्योग को इस क्षेत्र में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए व्यापक अवसर मिलेंगे।

इसके अतिरिक्त, दोनों पक्ष ओमान की अंशदायी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू होने के बाद सामाजिक सुरक्षा समझौते पर भविष्य में चर्चा करने के लिए सहमत हुए हैं। यह श्रमिकों की आवाजाही एवं श्रमिक संरक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को बताता है। ओमान इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और यह भारतीय वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए व्यापक पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक पहुंचने का एक प्रमुख प्रवेश द्वार है। ओमान में लगभग सात लाख भारतीय नागरिक रहते हैं। भारत को ओमान से प्रतिवर्ष लगभग दो अरब अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त होती है। भारतीय उद्यमों ने ओमान में अपनी मजबूत उपस्थिति स्थापित की है, जहां विभिन्न क्षेत्रों में 6,000 से अधिक भारतीय प्रतिष्ठान कार्यरत हैं। भारत को अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 के बीच ओमान से 61.554 करोड़ अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। ब्रिटेन के बाद पिछले छह महीनों में हस्ताक्षरित यह दूसरा व्यापार समझौता है। यह उन विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार समझौते करने की रणनीति का हिस्सा है जो हमारे श्रम-प्रधान हितों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं और भारतीय व्यवसायों के लिए अवसर प्रदान करती हैं। यह खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के सदस्य देश के साथ भारत का दूसरा व्यापार समझौता है।

पीएम मोदी ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित

ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने भारत-ओमान संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को 'ऑर्डर ऑफ ओमान' पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को दोनों देशों की सदियों पुरानी मित्रता को समर्पित किया और इसे भारत और ओमान के 1.4 बिलियन लोगों के बीच के स्नेह और प्रेम का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री की ओमान यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, इस सम्मान का प्रदान किया जाना इस अवसर और रणनीतिक साझेदारी को विशेष महत्व देता है। सुल्तान काबूस बिन सईद द्वारा 1970 में स्थापित, ऑर्डर ऑफ ओमान चुनिंदा वैश्विक नेताओं को सार्वजनिक जीवन और द्विपक्षीय संबंधों में उनके योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने निर्णायक कार्रवाई की क्षमता का सशक्त प्रदर्शन किया : रक्षा मंत्री

नई दिल्ली. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान सशस्त्र बलों ने भारत की उच्च-प्रभावशाली और अल्प समय में निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता का सशक्त प्रदर्शन किया। उन्होंने भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को तकनीकी रूप से उन्नत, परिचालन में चुस्त, रणनीतिक दृष्टि से आत्मविश्वासी और भविष्योन्मुखी सैन्य बल बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह निरंतर बदलते वैश्विक परिवेश में राष्ट्रीय हितों की प्रभावी रक्षा कर रही है। वे 18 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित वायु सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन के दौरान आतंकी शिविरों को नष्ट करने में भारतीय वायु सेना द्वारा प्रदर्शित साहस, गति एवं सटीकता की सराहना की और हमलों के उपरांत पाकिस्तान की ‘गैर-जिम्मेदाराना प्रतिक्रिया’ का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए भी वायु सेना की प्रशंसा की। उन्होंने सशस्त्र बलों, विशेष रूप से वायु रक्षा क्षमताओं पर जनता के गहरे विश्वास को रेखांकित किया। राजनाथ सिंह ने कहा, ‘आमतौर पर जब दुश्मन हमला करता है तो लोग सुरक्षित स्थानों की ओर रुख करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी सेना ने भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया, तब भारत के नागरिक शांत रहे और उन्होंने अपनी दैनिक गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रखीं। यह हमारी परिचालन तैयारियों पर प्रत्येक भारतीय के अटूट भरोसे का प्रमाण है।’ रक्षा मंत्री ने निर्णायक बढ़त बनाए रखने के लिए शत्रु की आक्रामक एवं रक्षात्मक क्षमताओं की गहन समझ के महत्व पर बल देते हुए कमांडरों से ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेने तथा भविष्य की प्रत्येक चुनौती से निपटने के लिए सतर्क और सदैव तैयार रहने का आग्रह किया।

सीमा पार से संचालित तस्करी कार्टेल का अमृतसर में पर्दाफाश

4.5 किलो हेरोइन, एक पिस्तौल सहित 3 काबू

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़/अमृतसर

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने हेरोइन और अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल तीन नशा तस्करों को 4.5 किलो हेरोइन और एक .30 बोर पिस्तौल सहित गिरफ्तार करके सीमा पार से संचालित नशा तस्करी कार्टेल का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गुरविंदर सिंह उर्फ गोपी (23) निवासी गांव शाहवाला (फिरोजपुर), तिलक उर्फ शिबू (18) जो राजीव गांधी विहार, जालंधर का निवासी है लेकिन वर्तमान में अमृतसर के मुस्तफाबाद में रहता है तथा दलजीत सिंह उर्फ लाला (20), जो गांव नौशहरा ढल्ला का निवासी है और वर्तमान में अमृतसर के गांव मुस्तफाबाद में रहता है, के रूप में हुई है।

ऑपरेशन संबंधी विवरण साझा करते हुए, पुलिस कमिश्नर (सी.पी.) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि आरोपी गुरविंदर सिंह उर्फ गोपी को 1.5 किलो हेरोइन और एक .30 बोर पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने दो अन्य साथियों की संलिप्तता का खुलासा किया, जिससे आगे की बरामदगियां हुईं। भुल्लर ने कहा कि उक्त खुलासे के आधार पर पुलिस ने दो अन्य आरोपियों, जिनकी पहचान तिलक उर्फ शिबू और दलजीत सिंह उर्फ लाला के रूप में हुई है, को नामजद करके गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 3 किलो और हेरोइन बरामद की। इस संबंध में पुलिस स्टेशन गेट हकीमा में एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 21-सी तथा 29 और असला एक्ट की धारा 25 (6, 7, 8) के तहत एफ.आई.आर. नंबर 345 दिनांक 12-12-2025 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

8000 रुपये रिश्वत लेता पटवारी विजीलैंस ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों काबू

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने पटवारी सर्कल बडाला, तहसील दसूहा, जिला होशियारपुर में तैनात राम सिंह पटवारी को शिकायतकर्ता से 8000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी ने यह रिश्वत बडाला गांव में शिकायतकर्ता की पैतृक जमीन का इंतकाल करने के बदले मांगी थी। शिकायतकर्ता की सूचना पर कार्रवाई करते हुए विजीलैंस ब्यूरो ने विजीलैंस ब्यूरो यूनिट जालंधर में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया और आरोपों की पुष्टि के बाद विजीलैंस की टीम ने जाल बिछाया तथा आरोपी पटवारी को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 8000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू कर लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून की संबंधित धाराओं के तहत पुलिस थाना विजीलैंस ब्यूरो, जालंधर रेंज में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को आज अदालत में पेश किया जाएगा।

लोकसभा से पास हुआ जीरामजी बिल

शिवराज बोले- कांग्रेस ने बापू के आदर्शों का किया नाश, हम भेदभाव नहीं करते

नई दिल्ली. संसद के हंगामेदार सत्र में लोकसभा ने गुरुवार को विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक, 2025 पारित कर दिया। इसके विरोध में विपक्षी सांसदों ने तीखे विरोध प्रदर्शन किए और सरकार पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के प्रावधानों को कमजोर करने का आरोप लगाया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का नाम एनआरईजीए में 2009 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए जोड़ा गया था। शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा में कहा कि अपनी बात कहना है और फिर जवाब नहीं सुनना भी ‘हिंसा’ है, विपक्ष के लोग बापू के आदर्शों के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग मनरेगा के नाम ढोंग करते हैं, मोदी सरकार काम करती है। चौहान ने प्रियंका गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि नाम रखने की सनक कांग्रेस की है, बहुत सारी योजनाओं के नाम नेहरू परिवार को महिमामंडित करने के लिए रखे गए।

शिवराज ने कहा कि यह आवश्यक हो गया था कि मनरेगा के पैसे का सही उपयोग हो, लूट बंद हो, पारदर्शिता हो, इसलिए इस योजना पर खुले मन से विचार किया गया और नई योजना लाने का फैसला हुआ। चौहान ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि शुरुआत में यह एनआरईजीए था और विधेयक में महात्मा गांधी का नाम शामिल नहीं था। बाद में, जब 2009 के आम चुनाव आए, तो कांग्रेस ने वोट पाने के लिए बापू गांधी का नाम याद किया। मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमजीएनईजीए को सही ढंग से और मजबूती से लागू किया।

आईसीपीई 2025 में 3000 से अधिक विद्यार्थियों ने लिया भाग

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद ने किया उद्घाटन

• **जालंधर ब्रीज.** रोपड़

3000 से अधिक विद्यार्थियों की सहभागिता के साथ अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी शिक्षा सम्मेलन 2025 (आईसीपीई 2025) का आयोजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ में किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित सम्मेलन का उद्घाटन भारत सरकार के प्रो. अजय कुमार सूद, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रो. राजीव आहूजा, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने प्रो. अजय कुमार सूद का संस्थान में स्वागत किया और उन्हें संस्थान में हो रहे अनुसंधान, नवाचार तथा प्रौद्योगिकी-आधारित पहलों की जानकारी दी। प्रो. सूद इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि भी हैं। बातचीत के दौरान प्रो. राजीव आहूजा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, उन्नत सामग्री, स्वच्छ ऊर्जा, कृषि प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा में नवाचार जैसे अग्रणी क्षेत्रों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के बढ़ते योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ये प्रयास सशक्त उद्योग सहभागिता और राष्ट्रीय अभियानों के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। प्रो. अजय कुमार सूद ने अनुसंधान, नवाचार और सामाजिक प्रभाव के प्रति संस्थान के समन्वित दृष्टिकोण की सराहना की और शैक्षणिक अनुसंधान को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जोड़ने के महत्व पर बल दिया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रो. राजीव आहूजा ने कहा, “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ में प्रो. अजय कुमार सूद का स्वागत करना हमारे लिए गौरव की बात है। एक अग्रणी अनुसंधान और नवाचार संस्थान के रूप में, हम भौतिकी और अंतर-विषयक विज्ञान में अपनी क्षमताओं को निरंतर सुदृढ़ कर रहे हैं, ताकि राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों का समाधान किया जा सके। आईसीपीई 2025 अनुसंधान-आधारित शिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भौतिकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।” प्रो. राजीव आहूजा, जो स्वयं एक प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञानी हैं और जिनका शोध अनुभव अत्यंत व्यापक है, ने संस्थान में मौलिक एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी अनुसंधान पर विशेष बल दिए जाने की जानकारी साझा की। वे विश्व के सर्वाधिक उद्धृत शोधकर्ताओं में शामिल हैं और भारत व स्वीडन के शीर्ष पाँच सामग्री वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। उन्होंने प्रायोगिक और सैद्धांतिक भौतिकी, अंतर-विषयक सहयोग, अनुसंधान-आधारित शिक्षण तथा वैश्विक सहभागिता के माध्यम से भौतिकी शिक्षा को सशक्त बनाने हेतु चल रहे प्रयासों की रूपरेखा प्रस्तुत की।

प्रो. अजय कुमार सूद ने संकाय सदस्यों और सम्मेलन प्रतिभागियों से भी संवाद किया तथा आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, अनुवादात्मक अनुसंधान और नवाचार-आधारित विकास के माध्यम से भारत के विज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर अपने विचार साझा किए।

आईसीपीई 2025 के अंतर्गत 17 और 18 दिसंबर को सक्रिय शिक्षण, भौतिकी शिक्षा अनुसंधान, क्वांटम शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम शिक्षण तथा लैंगिक समानता जैसे विषयों पर पूर्ण सत्र और आमंत्रित व्याख्यान आयोजित किए गए। भारतीय भौतिकी शिक्षा में समावेशन पर केंद्रित एक प्रमुख पैनल चर्चा भी सम्मेलन का हिस्सा रही। 18 दिसंबर को सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण पद्म श्री से सम्मानित प्रो. एच. सी. वर्मा की खुली बातचीत रही, जिसमें मासाई विद्यालय के श्री प्रतीक शुक्ला, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ की प्रो. शिल्पी चौधरी तथा विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस संवाद को प्रतिभागियों से अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और इससे प्रयोगात्मक अधिगम, अवधारणात्मक स्पष्टता तथा भारत में भौतिकी शिक्षा के भविष्य पर गहन चर्चा हुई। आईसीपीई 2025, जो 16 से 20 दिसंबर तक चलने वाला पाँच-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, में 3000 से अधिक विद्यार्थी एक साथ जुड़े हैं। सम्मेलन के अभी दो दिन शेष हैं, जिनमें भौतिकी शिक्षा में नए रुझान, क्वांटम प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उद्योग-अकादमिक सहभागिता और भविष्य के लिए तैयार पाठ्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएँ जारी रहेंगी। आईसीपीई 2025 तथा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के इस उच्च-स्तरीय दौरे जैसे आयोजनों के माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ नवाचार-प्रेरित अनुसंधान, वैश्विक शैक्षणिक सहयोग और विज्ञान एवं अभियांत्रिकी शिक्षा में उत्कृष्टता के एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को और अधिक सुदृढ़ कर रहा है।

जिला परिषद और पंचायत समिति के नतीजे घोषित

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

राज्य चुनाव आयोग, पंजाब ने गुरुवार को 22 जिला परिषदों के 346 जोनों और 153 पंचायत समितियों के 2834 जोनों से सदस्यों के चुनाव के लिए आम चुनावों के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस संबंध में जिला परिषद चुनावों में आप ने 218 जोनों, कांग्रेस ने 62 जोनों, शिरोमणि अकाली दल ने 46 जोनों, बीजेपी ने 7 जोनों, बीएसपी ने 3 जोन और आईएनडी ने 10 जोनों से जीत प्राप्त की है।

इसी तरह, पंचायत समिति चुनावों में ‘आप’ ने 1529 जोनों, आईएनसी ने 611 जोन, शिरोमणि अकाली दल ने 449 जोन, बीजेपी ने 73 जोन, बीएसपी ने 28 जोन और आईएनडी ने 144 जोन से जीत हासिल की है। जिला परिषद और पंचायत समिति के जिलावार नतीजे संलग्न हैं।

दुबई में नया साल मनाने के टोटल कितने रुपए लगेंगे? 5 दिनों का ट्रिप प्लान!

Travelling दुबई में नया साल मनाना आपके लिए एक खूबसूरत अनुभव हो सकता है। सबसे खास बात ये है कि इसे आसानी से एक प्लान्ड बजट में कवर किया जा सकता है...

• **जालंधर ब्रीज** . फीचर

साल 2025 खत्म होने वाला है, और अभी से लोग नए साल के वेलकम की तैयारी में जुट गए हैं। आप अगर आप भी नए साल के वेलकम के लिए कोई फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इसके लिए दुबई बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।

यह शहर सिर्फ ऊँची इमारतों और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए ही नहीं, बल्कि साफ-सुथरे बीच, खूबसूरत मॉडर्न अट्रैक्शन, पुराने कल्चर और नए साल के शानदार सेलिब्रेशन के लिए भी जाना जाता है। दुबई में नया साल मनाना आपके लिए एक खूबसूरत अनुभव हो सकता है।

सबसे खास बात ये है कि इसे आसानी से एक प्लान्ड बजट में कवर किया जा सकता है। चलिए जानते 5 दिन के दुबई ट्रिप में आप क्या-क्या एंजॉय कर सकते है और इस ट्रिप का बजट कितना आयेगा।

दुबई के पहले दिन Downtown की खूबसूरती को महसूस करें

- दुबई ट्रिप के पहले दिन की शुरुआत आप डाउनटाउन से करें, जहाँ शहर की मॉडर्न लाइफ सबसे ज्यादा दिखाई देती है। सुबह 'म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर' और दुबई मॉल देखने जाएँ। ये दोनों जगहें आपको शहर के फ्यूचरिस्टिक और ग्लैमरस माहौल का पहला अनुभव देंगी। शाम को आप बुर्ज खलीफ़ा के टॉप व्यू प्वाइंट से पूरे शहर की खूबसूरती को देख सकते हैं। इसके बाद दुबई के फाउंटेन शो और Downtown Boulevard की नाइट वाइब्स आपकी शाम को और खास बना देंगी। अगर समय बचे तो आप मिरेकल गार्डन या ग्लोबल विलेज भी जा सकते हैं।

दूसरा दिन – JBR और मरीना का रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस

- दुबई में दूसरा दिन थोड़ा आराम और बीच वाइब के नाम कर दें। सुबह JBR बीच पर समय बिताएँ और मरीना मॉल में घूमकर वहाँ के कैफे और शॉप्स का मजा लें। शाम होते-होते JBR वॉक की लाइफ और कैफे हॉपिंग का मजा लें। इसके बाद स्कूटर से ब्लू वाटर आइलैंड जाना आपको एक अलग ही फील देगा, जहाँ से रात का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है।

तीसरा दिन – डेजर्ट सफारी का रोमांच

- सुबह आप आया यूनिवर्स या स्की दुबई में से किसी एक जगह जाएँ। ये दोनों इनडोर फन के लिए बेहतरीन हैं और इन्हें एंजॉय करने के बाद एमिरेट्स मॉल में घूमने के लिए जाएं। दोपहर और शाम का पूरा समय डेजर्ट सफारी को दें, जिसमें dune bashing, ATV राइड, sand boarding, डांस शो और डिनर शामिल होता है। यह दुबई ट्रिप का सबसे यादगार पार्ट होगा।

चौथा दिन – ओल्ड दुबई की सादगी और कल्चर

- एक दिन दुबई के पुराने हिस्से को जरूर देना चाहिए। सुबह दुबई फ्रेम देखने जाएँ या फिर बुरजुमान मॉल में थोड़ी बहुत शॉपिंग करें। शाम को दुबई सूक, गोल्ड सूक और अल सीफ की खूबसूरत गलियों में चलकर पुराने दुबई की खूबसूरती को महसूस करें। यह इलाका बहुत ही एस्थेटिक है। इसके बाद क्रिक एरिया और बोट क्रॉसिंग के छोटे सफर के साथ दिन को पूरा करें।

पाँचवाँ दिन – पॉम जुमेराह का खूबसूरत अनुभव

- दुबई ट्रिप के अंतिम दिन पॉम जुमेराह जाएँ। सुबह पूरे आइलैंड का खूबसूरत नजारा देखें और औरा स्काईपूल की शानदार एंबिएंस का आनंद लें। शाम को The Pointe की रोशनी और फाउंटेन शो का आनंद उठाएं। इसके बाद मोनोरेल राइड लेकर पाम के आखिरी पॉइंट तक पहुँचें और इस खूबसूरत आइलैंड का पूरा चार्म महसूस करें।

5 दिन के दुबई ट्रिप का पूरा खर्च

- दुबई की पाँच दिन की यात्रा का औसत खर्च लगभग 59,000 से 64,000 रुपये के बीच आता है। राउंडट्रिप फ्लाइट लगभग 20,000 रुपये में मिल जाती है। वीजा का खर्च लगभग 6500 रुपये है, लेकिन अगर आपके पास US वीजा है, तो सिर्फ 2500 रुपये ही लगेंगे। अगर आप ट्विन शेयरिंग में रूम लेते हैं, तो पाँच रातों के होटल का खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 12,500 रुपये पड़ता है।

खाने का खर्च रोज 1500 से 2500 रुपये के बीच आता है, जो कुल मिलाकर लगभग 7500 से 12,500 रुपये होता है। सात दिनों का NOL कार्ड लगभग 2530 रुपये में मिल जाता है, जिससे शहर में घूमना आसान हो जाता है। सभी एक्टिविटीज मिलाकर लगभग 10,000 रुपये और थोड़ा बहुत इधर उधर का खर्च लगभग 1000 रुपये जोड़कर कुल बजट लगभग 60 से 64 हजार रुपए के बीच बैठा जाता है।

LIFESTYLE

डिटर्जेंट से रहें सावधान! कैंसर डॉक्टर बोले- गंभीर बीमारियों से बचना है तो चुनें ये सुरक्षित विकल्प

कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ. तरंग कृष्णा, ने लोगों को चेताया है कि रोजाना इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट और क्लीनर व्यक्ति के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं, जिसमें कैंसर का नाम भी शामिल है।

• **जालंधर ब्रीज** . फीचर

सेहतमंद बने रहने का सबसे अच्छा तरीका है अच्छी हाइजीन बनाए रखना। जिसके लिए व्यक्ति रोज नहाने से लेकर साफ धुले हुए कपड़े तक पहनता है। दरअसल, ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि घर में कपड़े धोने से लेकर घर को साफ करने वाले डिटर्जेंट और क्लीनर आपकी सेहत के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। इनका नियमित इस्तेमाल कपड़ों और घर में फ्रेशनेस बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं रोजाना इस्तेमाल होने वाले इन डिटर्जेंट और क्लीनर में कई बार कुछ ऐसे केमिकल्स छिपे हुए होते हैं, जो धीरे-धीरे व्यक्ति की सेहत को नुकसान पहुंचाकर हार्मोन बैलेंस बिगाड़ने के साथ कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ाते हैं।

क्या कहते हैं कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ. स्वपनिल?

22 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ. स्वपनिल, ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके लोगों को चेताया है कि रोजाना इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट और क्लीनर व्यक्ति के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं, जिसमें कैंसर का नाम भी शामिल है।

हार्मोनल असंतुलन

कैंसर इम्यूनोथेरेपी में एक्सपर्ट डॉ. तरंग कृष्णा कहते हैं कि अकसर लोगों को कपड़ों और घर में इस्तेमाल होने वाले कई प्रोडक्ट्स सुरक्षित और साफ-सुथरा लगते हैं। लेकिन उनमें छिपे केमिकल्स शरीर के लिए धीमा जहर की तरह काम कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स की खुशबू अक्सर हानिकारक फ्थेलेट्स (phthalates) को छिपाती है, जो समय के साथ हार्मोनल असंतुलन का कारण तक बन सकती है।

कैंसर का खतरा

डॉ. स्वपनिल कहते हैं कि कुछ डिटर्जेंट्स में फॉर्मेल्डिहाइड और यहां तक कि बेंजीन जैसे पदार्थ भी हो सकते हैं, जो सांस की तकलीफ, ब्रॉन्काइटिस पैदा करने के साथ कैंसर का खतरा भी काफी बढ़ा देते हैं।

डिटर्जेंट और क्लीनर के सुरक्षित विकल्प

डॉ. स्वपनिल डिटर्जेंट और क्लीनर में छिपे इन जोखिमों को कम करने के लिए प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्प अपनाने की सलाह देते हैं। डॉ. स्वपनिल कहते हैं कि ऐसे डिटर्जेंट चुनें जो फ्रेगरेंस-फ्री या नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स से बने हों। इसके अलावा हमेशा डिटर्जेंट और क्लीनर खरीदते समय उसका लेबल जरूर चेक करें। फ्थेलेट्स, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन या सिंथेटिक फ्रेगरेंस से बचें। इको-फ्रेंडली और प्लांट-बेस्ड डिटर्जेंट्स ट्राई करें। घरेलू विकल्प जैसे साबुन नट्स (रीठा), बेकिंग सोडा या विनेगर से बने क्लीनर इस्तेमाल करें। कम केमिकल वाले प्रोडक्ट्स चुनकर खुद और परिवार की सेहत की रक्षा करें।

सलाह – डिटर्जेंट और क्लीनर चुनते समय किए गए ये छोटे-छोटे बदलाव लंबे समय में आपकी सेहत पर बड़ा फर्क डाल सकते हैं। किसी भी तरह की कोई स्वास्थ्य समस्या महसूस होने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

मटर डालकर खूब टेस्टी बनती हैं ये 7 सब्जियां, सर्दियों में जरूर करें ट्राई

रोज वाली सब्जियां खा कर थोड़े बोर हो जाएं, तो उनमें जरा से मटर के दाने एड कर दें, स्वाद नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि किन-किन सब्जियों में आप मटर डालकर बना सकती हैं।

• **जालंधर ब्रीज.** रेसिपी

मटर डालकर टेस्टी बनती हैं ये सब्जियां : सर्दियों के मौसम में हरी-भरी मटर बाजार में खूब आती है। इससे कई डिशेज बनाई जाती हैं और कई सब्जियों में भी डाला जाता है। रोज वाली सब्जियां खा कर थोड़े बोर हो जाएं, तो उनमें जरा से मटर के दाने एड कर दें, स्वाद नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि किन-किन सब्जियों में आप मटर डालकर बना सकती हैं। मटर डालकर टेस्टी बनती हैं ये सब्जियां

सर्दियों के मौसम में हरी-भरी मटर बाजार में खूब आती है। इससे कई डिशेज बनाई जाती हैं और कई सब्जियों में भी डाला जाता है। रोज वाली सब्जियां खा कर थोड़े बोर हो जाएं, तो उनमें जरा से मटर के दाने एड कर दें, स्वाद नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि किन-किन सब्जियों में आप मटर डालकर बना सकती हैं।

गोभी मटर का कॉम्बो ट्राई करें : सर्दियों में फूलगोभी और मटर का क्लासिक कॉम्बो आपने ट्राई किया ही होगा। जरा से मटर डलने से सब्जी का पूरा स्वाद ही बदल जाता है। गोभी की सूखी सब्जी बनाएं या ग्रेवी वाली, मटर डालना ना भूलें। सर्दियों में ये सब्जी परफेक्ट लगती है।

आलू मटर की सब्जी : आलू की सब्जी में जरा से मटर डालकर बहुत ही स्वाद सब्जी बनकर तैयार होती है। पूड़ी-पराठे के साथ इसका टेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल लगता है। जरा से हींग जीरा का तड़का और कुछ बेसिक मसाले, सर्दियों में आपकी परफेक्ट सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी।

पत्तागोभी में डालें मटर : पत्तागोभी की सूखी सब्जी में भी मटर के दाने काफी टेस्टी लगते हैं। इससे सब्जी की ड्राइनेस एकदम बैलेंस हो जाती है और स्वाद काफी एन्हांस हो जाता है। ये सूखी सब्जी पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है।

भिंडी मटर मसाला : कुछ अलग ट्राई करना है तो एक बार भिंडी मटर मसाला की रेसिपी जरूर बनाकर देखें। तेल में जीरा, अदरक लहसुन, करी पत्ता डालकर भून लें, फिर मटर डालें। कुछ देर में भिंडी एड करें और बेसिक मसाले मिलाएं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है।

आलू गाजर और मटर : विंटर्स में आलू गाजर और मटर का कॉम्बिनेशन नेक्स्ट लेवल लगता है। पराठे के साथ ये मसालेदार सूखी सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मटर डलने से गाजर आलू की सब्जी बैलेंस हो जाती है, जिससे स्वाद बहुत एन्हांस हो जाता है।

लौकी मटर की सब्जी : लौकी मटर की सब्जी भी एक बार आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। सर्दियों में इसे खाने का मजा ही कुछ और है। इसे आप प्रेशर कुकर में भी झटपट बना सकती हैं। काफी टेस्टी और बैलेंस सब्जी लगती है।

मूली मटर की सब्जी : मूली के साथ जब मटर मिक्स होती है, तो उसकी कड़वाहट और स्मेल दोनों कम हो जाती है। खाने में ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। अगर अभी तक आपने मटर के साथ मूली की सब्जी ट्राई नहीं की है, तो इस विंटर सीजन जरूर बनाकर देखें।

बच्चों की धूप से दोस्ती क्यों जरूरी? इस विटामिन की कमी है खतरनाक

PARENTING

जालंधर ब्रीज (फीचर) . विटामिन डी को 'सनशाइन विटामिन' कहा जाता है, क्योंकि यह धूप में रहने से शरीर में प्राकृतिक रूप से बनता है। हालांकि आजकल के इनडोर लाइफस्टाइल कल्चर की वजह से ज्यादातर बहुत छोटे बच्चों को धूप से दूर रखा जाता है। जो टॉडलर्स पहले घंटों बाहर खेलते थे, वे आजकल ज्यादातर समय घर, डे-केयर या गैजेट्स से ही घिरे रहते हैं। यही वजह है कि बहुत कम उम्र में ही छोटे बच्चों को भी विटामिन डी की कमी देखने को मिल रही है।

बच्चों में विटीमिन डी की कमी के कारण : मधुकर रेनबो चिल्ड्रेन हॉस्पिटल की बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मेधा कहती हैं कि धूप विटामिन D का सबसे भरोसेमंद स्रोत है, लेकिन कई माता-पिता गर्मी, प्रदूषण या सुरक्षा कारणों से बच्चों को बाहर ले जाने से बचते हैं। ऊपर से सनस्क्रीन का अधिक इस्तेमाल भी विटामिन डी बनने की प्रक्रिया को कम कर देता है। इसके अलावा, खिड़की से आने वाली धूप से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कांच UVB किरणों को रोक देता है। खाने की आदतें भी इसमें अहम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे फोर्टिफाइड दूध, अंडे की जर्दी या मछली जैसे विटामिन D से भरपूर खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते हैं।

विटामिन D की कमी से होने वाली समस्याएं : विटामिन D की कमी से बच्चों की इम्युनिटी कमजोर हो सकती है, हड्डियों और मसल्स का विकास प्रभावित हो सकता है, नींद और मूड पर भी असर पड़ सकता है। ज्यादा कमी होने पर चलने में देरी, बार-बार संक्रमण होना, हड्डियों का कमजोर होना या रिकेट्स जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

विटामिन D की कमी पूरी करने में मदद करेंगे ये टिप्स : सीके बिरला अस्पताल में नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. पूनम सिदाना कहती हैं कि रोजाना 15-20 मिनट की सुरक्षित सुबह की धूप, विटामिन डी से भरपूर या फोर्टिफाइड फूड्स और डॉक्टर की सलाह से दिए गए सप्लीमेंट्स बच्चों में इस कमी को दूर करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना भी बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि , ये सभी चीजें इस विटामिन की कमी को पूरा करने में अपने आप में काफी नहीं है। बच्चों की हड्डियों में विटामिन डी और कैल्शियम को सही तरह से असर करने के लिए शारीरिक गतिविधि भी उतनी ही जरूरी है।

***डिस्क्लेमर :** इस लेख में दी गई सूचना पूरी तरह सोशल मीडिया रील पर आधारित है। जालंधर ब्रीज इसकी सत्यता और सटीकता की जिम्मेदारी नहीं लेता है।*

ज्यादातर डायबिटीज के मरीज करते हैं ये काम, डॉक्टर ने गिनाई खराब आदतें जो बढ़ा देती हैं ब्लड शुगर

Health डायबिटीज के मरीजों को अपने खान-पान का खास ख्याल रखना पड़ता है, वरना उनका शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है। डायबिटीज होने से कई अन्य बीमारियों के होने का खतरा रहता है। डॉक्टर जोशी का कहना है कि...

• **जालंधर ब्रीज.** हेल्थ केयर

डायबिटीज की बीमारी आजकल काफी आम हो चुकी है। कम उम्र में ही लोगों को ये बीमारी हो रही है और इसका सीधा कनेक्शन खराब लाइफस्टाइल और गलत खान-पान से है। डायबिटीज होने के बाद मरीजों को कई चीजों से परहेज पड़ता है और इसमें ब्लड शुगर को भी कंट्रो में रखना पड़ता है। अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो ये सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। बेंगलुरु की डॉक्टर अखिला जोशी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह हाई ब्लड शुगर करने वाली 5 खराब आदतों के बारे में बता रही हैं। अगर आप इन आदतों से खुद को बचा लेते हैं, तो डायबिटीज होने के बाद भी कभी ब्लड शुगर हाई नहीं होगी।

***डिस्क्लेमर :** यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।*

क्या हैं खराब आदतें

- कम पानी पीना- डॉक्टर अखिला का कहना है कि वैसे तो आमतौर पर लोग कम पानी पीते हैं लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए पानी की मात्रा ज्यादा रखना जरूरी है। अगर आप कम पानी पीते हैं, तो ब्लड शुगर हाई रहता है और शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है। शरीर में पानी की कमी होने पर किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे इसके फेल होने का खतरा रहता है।
- ज्यादा खाना- आप परहेज कर रहे हैं और हेल्दी खाना खाते हैं लेकिन ज्यादा खा रहे हैं। तो ब्लड शुगर हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। हमेशा कम लेकिन हेल्दी खाना खाएं। ज्यादा चावल या रोटी खाने से आपकी शुगर तेजी से बढ़ेगी और इसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा।
- कम नींद- डायबिटीज के मरीजों के लिए नींद पूरी होना काफी जरूरी है। अगर आप 6 घंटे से भी कम सोते हैं, तो शुगर लेवल बढ़ा रहेगा और इंसुलिन लेना पड़ेगा। कम नींद लेने से खाने की इच्छा बढ़ती है और स्ट्रेस बना रहता है। साथ ही कम नींद से शरीर में दर्द भी होता है और थकान भी महसूस होती है।
- मील स्किप- डायबिटीज पेशेंट्स को कभी भी अपना नाश्ता, लंच या फिर डिनर स्किप नहीं करना चाहिए। इसे स्किन करने से आपकी शुगर स्पाइक हो सकती है। खाना नहीं खाने से मेटाबॉलिज्म पर असर होता है और आप ओवरईटिंग करने लगते हैं। ओवरईटिंग करने से शुगर बढ़ती है।
- रूटीन चेकअप- ज्यादातर डायबिटीज पेशेंट्स को लगता है कि परहेज करने से शुगर कंट्रोल में रहेगी और वह अपना रूटीन चेकअप नहीं करवाते हैं। रूटीन चेकअप डायबिटीज पेशेंट्स को जरूर कराना चाहिए, इससे पता चलता है कि आपकी डायबिटीज किस लेवल पर है और इससे किसी और बॉडी पार्ट पर तो असर नहीं हो रहा। इसे टाइम से करवाएं।

संरक्षा, दायित्व और जन विश्वास - नए अधिनियम से क्या हासिल होगा

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

जनता का विश्वास हमेशा से भारत के परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला रहा है। देश के सतत, समतापूर्ण और ऊर्जा-सुरक्षित विकास के दृष्टिकोण में यह आधार निहित है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग अत्यधिक संरक्षा, निर्विवाद उत्तरदायित्व और पारदर्शी संचार के साथ किया जाए। संरक्षा, दायित्व और जन विश्वास के स्तंभ केवल अमूर्त आदर्श नहीं हैं; ये भारत के परमाणु उद्योग के व्यावहारिक आधार हैं।

जैसे-जैसे हम परमाणु ऊर्जा के लिए एक नए विधायी ढाँचे पर विचार कर रहे हैं, यह पूछना ज़रूरी है कि यह नए अधिनियम से क्या हासिल होगा? मेरे विचार से, इसका उत्तर इन्हीं आधारों को मज़बूत करने में निहित है। इस कानून से अपेक्षा है कि यह जनता के विश्वास से समझौता किए बिना संरक्षा और सशक्तिकरण प्रदान करे, सरलीकरण और सुरक्षा प्रदान करे, नवाचार को प्रोत्साहित करे।

संरक्षा - पूर्णता की संस्कृति को संस्थागत बनाना

परमाणु प्रौद्योगिकी में संरक्षा डिज़ाइन का एक अनिवार्य अंग ही नहीं, बल्कि यह इसका मूल दर्शन होना चाहिए। ट्रॉम्बे में भारत के पहले अनुसंधान रिएक्टरों से लेकर स्वदेशी 700 मेगावाट दाबित भारी पानी रिएक्टरों और अगली पीढ़ी के प्रगत रिएक्टरों तक, डिज़ाइन हमेशा गहन संरक्षा और निश्चेष्ट संरक्षा विशेषताओं द्वारा निर्देशित रही हैं।

जब हमने प्रगत भारी पानी रिएक्टर (AHWR) की कल्पना की थी, तो हमारा लक्ष्य न केवल थोरियम के उपयोग को प्रदर्शित करना था, बल्कि यह भी प्रदर्शित करना था कि एक रिएक्टर इसके ऑपरेटर के हस्तक्षेप के बिना भी सुरक्षित रह सकता है - एक ऐसी डिजाइन जो स्वत: सुरक्षित (walk-away safe) हो। वास्तव में, संरक्षा परमाणु ऊर्जा परिनियोजन का एक अभिन्न अंग है। नए अधिनियम को, निश्चित रूप से, यह गारंटी देनी चाहिए कि संरक्षा-संस्कृति जारी रहे। इसे उच्चतम संरक्षा मानकों के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करनी चाहिए और नियामक संस्थानों की स्वायत्तता, अधिकार और जवाबदेही को मजबूत करना चाहिए। इसे आवश्यकतानुसार प्रौद्योगिकी उन्नयन और पारदर्शी संरक्षा समीक्षाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसे प्रचालन प्रदर्शन पर सूचना के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देना चाहिए। किसी भी उद्योग में विशेषकर परमाणु ऊर्जा के मामले में तो और भी ज़्यादा, संरक्षा एक स्थिर लक्ष्य नहीं है। इसे एक ऐसी संस्कृति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसका निरंतर पोषण किया जाना चाहिए। ख़ास तौर पर परमाणु पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में, इस संस्कृति को एक संस्थागत फ्रेमवर्क के ज़रिए मज़बूत किया जाना चाहिए।

दायित्व - स्पष्टता के साथ उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना

नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम (सीएलएनडी अधिनियम) एक

डा. रतन कुमार सिन्हा
(पूर्व सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं पूर्व अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग)

अग्रणी कदम रहा है जिसने तीन महत्वपूर्ण हितों को संतुलित किया है: जनता की संरक्षा, आपूर्तिकर्ताओं को आश्वासन और ऑपरेटरों का विश्वास। इसने दोष-रहित दायित्व सिद्धांत को प्रतिपादित किया और यह सुनिश्चित किया कि ऑपरेटर की ज़िम्मेदारी स्पष्ट और निर्देशित रहे।

ऊर्जा परिदृश्य और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास ने संबंधित संस्थाओं की देनदारियों पर अधिक स्पष्टता को आवश्यक बना दिया है। इस तरह के संशोधन किसी भी परिपक्व क्षेत्र की स्वाभाविक प्रगति का हिस्सा हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि शासन का फ्रेमवर्क वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक अपेक्षाओं के साथ तालमेल बनाए रखे।

नए अधिनियम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शासन का फ्रेमवर्क निष्पक्ष, स्पष्ट हो और संदेह रहित बना रहे, साथ ही जवाबदेही की एक सुपरिभाषित श्रृंखला भी बनाए रखे। इसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि दायित्व का मूल्यांकन करने की व्यवस्था देश में परमाणु तैनाती की सीमा और पैमाने के अनुरूप हो। एक आधुनिक दायित्व व्यवस्था को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि संरक्षा और ज़िम्मेदारी विकास के साथ-साथ चलती हैं।

जन विश्वास - प्रगति की आधारशिला

दुनिया भर में परमाणु उद्योग के उत्कृष्ट संरक्षा रिकॉर्ड के बावजूद, परमाणु ऊर्जा के प्रति जनता का दृष्टिकोण अक्सर वैज्ञानिक तथ्यों की तुलना में धारणाओं से अधिक प्रभावित होता रहा है। कुछ साल पहले मैंने जिस पुस्तक का सह-लेखन किया था, "द अनरीज़न्ड फियर ऑफ़ रेडिएशन", ऐसी ही भ्रांतियों को दूर करने का एक प्रयास था। यह पुस्तक बताती है कि नियंत्रित और सुव्यवस्थित वातावरण में विकिरण, किसी भी अन्य तकनीक जितना ही सुरक्षित है जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में नियमित रूप से आत्मविश्वास से करते हैं।

जनता का विश्वास केवल पारदर्शिता और जनता के साथ संवाद के माध्यम से ही अर्जित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब नागरिक देखते हैं कि परमाणु विज्ञान रेडियोथेरेपी के माध्यम से जीवन बचा रहा है, उत्परिवर्तन प्रजनन के माध्यम से फसलों को बढ़ा रहा है या विकिरण शुद्धिकरण के माध्यम से सुरक्षित जल उपलब्ध करा रहा है, तो वे परमाणु ऊर्जा के मानवीय पहलू से जुड़ने लगते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान, हमने नई आउटरीच रणनीतियों की शुरुआत करके इस दिशा में कई प्रयास किए, जिसके परिणामस्वरूप 2015 की गणतंत्र दिवस परेड में परमाणु ऊर्जा विभाग की झांकी प्रदर्शित की गई और प्रसारण व सोशल मीडिया पर उपस्थिति दर्ज कराई गई। ये कदम दिखावटी नहीं थे; इनका उद्देश्य विज्ञान और समाज के बीच की दीवार को हटाना था।

यदि नया अधिनियम नागरिकों के साथ खुले संवाद को बढ़ावा दे पाता है, तो यह समाज के साथ विज्ञान के सामाजिक संबंधों को पुनर्परिभाषित करेगा। ऐसा करके, यह हमारे चिरस्थायी आदर्श वाक्य: राष्ट्र की सेवा में परमाणु, की भावना को साकार करेगा। नए अधिनियम से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार के संदेश सार्वजनिक प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाएं, शैक्षिक जागरूकता को प्रोत्साहित करें तथा नागरिकों के साथ संवाद को संस्थागत कार्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाएं।

नए अधिनियम में क्या गारंटी होनी चाहिए

यदि 1962 के प्रथम परमाणु ऊर्जा अधिनियम ने क्षमता निर्माण के मूल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था, तो नए अधिनियम का उद्देश्य आत्मविश्वास बढ़ाना और परमाणु प्रौद्योगिकी की बड़े पैमाने पर तैनाती करना होना चाहिए। इसमें उस राष्ट्र की परिपक्वता प्रतिबिंबित होनी चाहिए जिसने जटिल तकनीकों में महारत हासिल की है और जिम्मेदार आचरण के माध्यम से वैश्विक सम्मान अर्जित किया है। नए अधिनियम को विज्ञान और समाज के बीच पारस्परिक आश्वासन की यह गारंटी देनी चाहिए कि :-

संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, दायित्व (देनदारियां) हमेशा न्यायसंगत और पारदर्शी रहेगा, और जनता का विश्वास हर निर्णय के केंद्र में रहेगा। जब ये गारंटियां न केवल कानून में, बल्कि संस्थागत व्यवहार में भी निहित होंगी, तो भारत का परमाणु भविष्य सुदृढ़ आधार पर खड़ा होगा।

विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम

भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए यह एक परिवर्तन का दौर है। बड़े विद्युत संयंत्रों के अलावा, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और प्रगत थोरियम प्रणालियाँ परमाणु ऊर्जा की पहुँच का विस्तार करेंगी। इसलिए नए अधिनियम को एक ऐसे फ्रेमवर्क की गारंटी देनी चाहिए जो प्रौद्योगिकियों के तेज़ उपयोग को सुगम बनाए और साथ ही स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण को प्रोत्साहित करे। इसमें नियामकों, प्रचालकों और उद्योग के बीच निर्बाध समन्वय और भविष्य के नवाचारों को शामिल करने के लिए लचीलापन सुनिश्चित करना चाहिए। संक्षेप में, नए अधिनियम को परमाणु पुनर्जागरण के लिए एक अनुकूल पृष्ठभूमि तैयार करनी चाहिए जो भारत में जलवायु लक्ष्यों और विकसित भारत @2047 बनने की राह में स्वच्छ-ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को विश्व का अग्रणी देश बनने की आकांक्षाओं के अनुरूप हो।

63 किमी लंबी भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नई रेल लाइन हेतु ₹6,753 करोड़ मंजूर

बिलासपुर-मनाली-लेह रणनीतिक रेल लाइन : 489 किमी लंबी परियोजना में 270 किमी सुरंगें, लागत ₹1.31 लाख करोड़

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी (63 किमी) नई रेल लाइन परियोजना को लागत-साझाकरण के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें केंद्र सरकार की 75% तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की 25% हिस्सेदारी निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण की ₹70 करोड़ रुपये से अधिक की लागत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी। परियोजना का विस्तृत अनुमान ₹6,753 करोड़ रुपये की लागत पर स्वीकृत किया गया था, जिसमें ₹1,617 करोड़ रुपये भूमि लागत के रूप में शामिल है।

इस परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश में कुल 124 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसके मुकाबले राज्य सरकार ने केवल 82 हेक्टेयर भूमि ही उपलब्ध कराई है। उपलब्ध भूमि पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, जबकि बिलासपुर से बेरी तक की भूमि अभी तक राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित नहीं की गई है। भूमि की अनुपलब्धता के कारण परियोजना की प्रगति पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

परियोजना पर अब तक कुल ₹5,252 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। लागत-साझाकरण समझौते के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार को ₹2,711 करोड़ रुपये का योगदान करना था, किंतु अब तक केवल ₹847 करोड़ रुपये ही जमा किए गए हैं। इस प्रकार, राज्य सरकार के ऊपर ₹1,863

करोड़ रुपये की राशि अभी भी बकाया है। अपने हिस्से की राशि समय पर उपलब्ध न कराने से परियोजना की गति प्रभावित हुई है।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबद्धताओं को पूर्ण रूप से पूरा न करने के कारण परियोजना की प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई है। परियोजना को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाने हेतु राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। भारत सरकार इस परियोजना को शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिए पूर्णतः तत्पर है, किन्तु इसकी सफलता हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किए जाने पर निर्भर करती है।

हिमाचल प्रदेश राज्य में पूर्णतः या आंशिक रूप से आने वाली अवसंरचना परियोजनाओं एवं सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2009-14 के दौरान इन परियोजनाओं पर औसतन ₹108 करोड़ प्रति वर्ष व्यय किया जाता था। इसके विपरीत, वर्ष 2025-26 में इन कार्यों के लिए बजट बढ़ाकर ₹2,716 करोड़ कर दिया गया है, जो पूर्व आवंटन की तुलना में 25 गुना से अधिक वृद्धि को दर्शाता है।

हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए, नांगल बांध - ऊना - अंदौरा- दौलतपुर चौक (60 किमी) खंड का नांगल बांध - तलवारा - मुकेरियां नई लाइन परियोजना का कार्य शुरू कर दिया गया है। दौलतपुर चौक - करतोली पंजाब - तलवारा (52 किमी) खंड का कार्य भी शुरू हो गया है। इसके अलावा, चंडीगढ़-बद्दी नई लाइन (28 किमी) का कार्य भी 1540 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया है।

इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश में रेल संपर्क को बेहतर बनाने के लिए, बद्दी-घानाउली नई लाइन (25 किमी) का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है।

बिलासपुर-मनाली-लेह नई पाइपलाइन को रक्षा मंत्रालय द्वारा रणनीतिक पाइपलाइन के रूप में चिह्नित किया गया है। सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। यह परियोजना हिमालय के दुर्गम भूभाग से होकर गुजरती है, जो भूवैज्ञानिक आश्चर्यों और अनेक समस्याओं से भरा हुआ है। परियोजना की कुल लंबाई 489 किलोमीटर है, जिसमें 270 किलोमीटर लंबी सुरंगें भी शामिल हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की अनुमानित लागत ₹1,31,000 करोड़ है।

किसी भी रेलवे परियोजना की स्वीकृति अनेक मापदंडों और कारकों के विस्तृत आकलन पर निर्भर करती है, जिनमें प्रस्तावित मार्ग के संभावित यातायात का अनुमान, लाभप्रदता का विश्लेषण, प्रथम और अंतिम मील कनेक्टिविटी, छूटी हुई कड़ियों को जोड़ना, भीड़भाड़ वाली या संतृप्त लाइनों का विस्तार, तथा राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगें शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, रेलवे की परिचालन संबंधी आवश्यकताएँ, सामाजिक-आर्थिक विचार, तथा निधियों की समग्र उपलब्धता भी परियोजना स्वीकृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वहीं, किसी स्वीकृत रेलवे परियोजना के पूर्ण होने की प्रक्रिया कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे—राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, वन कटाई की अनुमति, उल्लंघनकारी उपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न अधिकारियों से वैधानिक स्वीकृतियाँ, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियाँ, परियोजना स्थल के आसपास की कानून-व्यवस्था की स्थिति, तथा परियोजना क्षेत्र में एक वर्ष में काम करने योग्य महीनों की संख्या। ये सभी तत्व मिलकर रेलवे परियोजनाओं की प्रगति और समयबद्ध निष्पादन को सीधे प्रभावित करते हैं। यह जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

भारत के टेक्सटाइल की नई ग्लोबल पोज़िशनिंग

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

जब हम भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं, तो हम केवल फैक्ट्री, मशीनों और फैशन की नहीं, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों की बात करते हैं, जिनकी ज़िंदगी कॉटन के खेतों, हैंडलूम, पावरलूम और सिलाई मशीनों से जुड़ी है।

पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस व्यापक सोच, दृढ़ संकल्प और निर्णायक नीतिगत सुधार को इस क्षेत्र ने देखा है, उससे आज टेक्सटाइल सेक्टर एक नए आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। आज जब हम टेक्सटाइल सेक्टर में लागू हालिया सुधारों के प्रभाव की बात करते हैं, तो यह केवल बदलाव नहीं, बल्कि किसानों, उद्यमियों, महिलाओं, बुनकरों, तकनीशियनों और युवाओं की नई संभावनाओं की कहानी है जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक टेक्सटाइल शक्ति बनाना है। यह लेख सिर्फ़ योजनाओं की सूची नहीं, बल्कि उस परिवर्तन की झलक है जिसे हम सब ने मिलकर आकार दिया है।

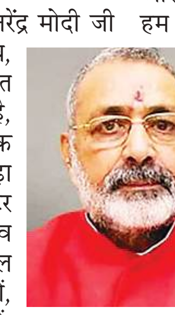

गिरिराज सिंह
(केंद्रीय वस्त्र मंत्री)

किसान-केंद्रित बदलाव : कॉटन की रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट और MSP में ऐतिहासिक वृद्धि

टेक्सटाइल क्षेत्र की जड़ें खेत में हैं और किसान इस यात्रा की पहली कड़ी हैं। इसलिए हमारी प्राथमिकता हमेशा यह रही कि कॉटन किसान को बाजार के उतार-चढ़ाव, दामों की अनिश्चितता और बिचौलियों की दबाव-प्रणाली से मुक्त किया जाए। यही कारण है कि 2004 से 2014 के बीच जहाँ सरकारी एजेंसियों द्वारा कुल 173 लाख कॉटन बेल्स की खरीद हुई, वहीं 2014 से 2024 के बीच यह बढ़कर 473 लाख कॉटन बेल्स पर पहुँची। यह लगभग 173% की वृद्धि है, जो दर्शाती है कि सरकार ने किसान को सिर्फ़ मौसमी प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि उसे स्थायी सुरक्षा दी।

इसी तरह MSP में सुधार भी किसानों को स्थिरता देने वाला बड़ा कदम रहा है। 2013-14 में कॉटन का MSP 3,700 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि 2025-26 में इसे बढ़ाकर 7,710 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। यह 108% की वृद्धि है, जो किसान की आय, सुरक्षा और आत्मविश्वास को मजबूत करती है। जब हम कहते हैं कि किसान हमेशा सुरक्षित है, तो यह सिर्फ़ बात भर नहीं, बल्कि इन वास्तविक आँकड़ों पर आधारित सच्चाई है कि सरकार पहले से अधिक मात्रा में कॉटन खरीद रही है और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कर रही है।

मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी: क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और न्यू ऐज फाइबर

सिर्फ़ ज़्यादा प्रोडक्शन ही काफ़ी नहीं, बेहतर क्वालिटी भी उतनी ही ज़रूरी है। इसी सोच के साथ ₹2,500 करोड़ का मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य केवल प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं, बल्कि कॉटन की गुणवत्ता को विश्व-स्तर तक पहुँचाना है। इस मिशन के तहत बेहतर बीज, वैज्ञानिक खेती, फार्म मैनेजमेंट और गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रियाएँ मजबूत की जा रही हैं। इसके साथ ही किसान को न्यू-एज फाइबर की तरफ प्रेरित करने का प्रयास भी किया जा रहा है ताकि भारत ग्लोबल वैल्यू-चेन में हाई क्वालिटी कॉटन और मिक्स्ड फाइबर के प्रमुख सप्लायर के रूप में उभरे।

जब हम भविष्य की बात करते हैं, तो पुनः स्पष्ट करना आवश्यक है कि टेक्सटाइल की अगली वृद्धि ट्रेडिशनल फाइबर पर ही आधारित नहीं होगी। इसी दिशा में सरकार ने फ्लैक्स, रैमी, सिसल और मिल्कवीड जैसे न्यू ऐज फाइबर को प्राथमिकता में रखा है।

आदिवासी महिलाओं की भूमिका और नेतृत्व

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

भारत विविध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन-पद्धतियों वाला समृद्ध देश है, और इसमें अनुसूचित जनजातियों की आबादी 10.45 करोड़ से अधिक है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% है।यह केवल जनसंख्या का आँकड़ा नहीं, बल्कि भारत की जीवंत, प्राचीन और बहुविध सांस्कृतिक धरोहर का अद्वितीय स्वरूप है। यह समुदाय न केवल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संवाहक रहा है, बल्कि अपनी समृद्ध परंपराओं, भाषा-भाषाई विविधता और मौलिक ज्ञान प्रणालियों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक पहचान को निर्मित करता रहा है। रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इनके पराक्रम, बुद्धिमत्ता और प्रकृति से गहरे संबंध का उल्लेख मिलता है।

फिर भी, लंबे समय तक आदिवासी समाज को मुख्यधारा के विकास से दूर रखा गया। उन्हें एक जीवित संस्कृति के संरक्षक के रूप में तो देखा गया, पर समान भागीदार के रूप में नहीं। विशेषकर आदिवासी महिलाओं के नेतृत्व, कौशल, सामाजिक समझ और समुदाय निर्माण में उनकी भूमिका को लंबे समय तक वह मान्यता नहीं मिली, जिसकी वे वास्तविक हकदार थीं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस सोच और

लेखिका : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार

व्यवस्था में स्पष्टत था उद्देश्य पूर्ण परिवर्तन देखने को मिला है। सरकार ने टोकनिज़्म (प्रतीकात्मक पहल) से आगे बढ़कर टार्गेटेड एम्पावरमेंट (लक्ष्य आधारित सशक्तिकरण) की नीति अपनाई है। जनजातीय समुदायों के सर्वांगीण विकास के प्रति यह प्रतिबद्धता इस बात का प्रमाण है कि भारत की विकास यात्रा में अब कोई भी समुदाय पीछे न रह जाए।" सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" का मंत्र इसी समावेशी दृष्टि का सशक्त उदाहरण बन चुका है।

इसी प्रतिबद्धता का प्रभाव बजट आवंटन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जनजातीय समुदायों के विकास हेतु कुल बजट 2024-25 में ₹10,237.33 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹14,925.81 करोड़ हो गया है, जो 45.79% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। यदि दीर्घकालीन दृष्टि से देखें, तो 2014-15 में ₹4,497.96 करोड़ के बजट के मुकाबले यह राशि पहले 2021-22 में ₹7,411 करोड़ तक पहुँची और अब यह वृद्धि 231.83% तक पहुँच गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए बढ़े हुए आवंटन से स्पष्ट है कि अब आदिवासी समुदाय, खासकर महिलाएँ, विकास की यात्रा में केवल लाभार्थी नहीं बल्कि नेतृत्वकारी भूमिका में हैं। भारत की आदिवासी महिलाएँ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की धुरी रही हैं। वे जल, जंगल और जमीन से जुड़ी पारंपरिक जीवन व्यवस्थाओं की संरक्षक हैं और सामुदायिक निर्णय, संसाधन प्रबंधन और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज यह भूमिका केवल पारिवारिक और सामुदायिक स्तर तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि शासन व्यवस्था से लेकर नीति निर्माण तक दिखाई दे रही है। इस परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली प्रतीक यह है कि भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक आदिवासी महिला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसीन हैं।

सरकार ने आदिवासी महिलाओं के सामाजिक-सांस्कृतिक सशक्तिकरण, आर्थिक उत्थान एवं उनके नेतृत्व को संस्थागत आधार प्रदान करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे विकास केवल सुविधाओं का विस्तार न होकर, सम्मान, पहचान और आत्मनिर्भरता को भी सुनिश्चित करे।

भारत की पंचायतों के लिए यह समय नवाचार और उद्यमियों की तरह सोचने का है

जालंधर ब्रीज (नई दिल्ली) . 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ, ग्राम पंचायतों (जीपी) को जमीनी स्तर पर स्व-शासन के एक नए युग का सूत्रपात करने के लिए सशक्त बनाया गया। आशा थी कि वे वित्तीय रूप से सशक्त, राजनीतिक रूप से जिम्मेदार और नवोन्मेषी होंगे। हालांकि, तब से काफी प्रगति हुई है, लेकिन यह विज़न अब भी केवल आधा ही पूरा हुआ है। अनुच्छेद 243एच के तहत अपना राजस्व जुटाने का संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद, अधिकांश ग्राम पंचायतें अब भी वित्तीय दृष्टि से राज्य और केंद्र सरकारों के हस्तांतरणों पर निर्भर हैं। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के नवीनतम आंकड़ों और राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के 2025 के अध्ययन के अनुसार, स्व-संसाधन राजस्व (ओएसआर) पंचायत वित्त में केवल 6-7% का ही योगदान देता है। शेष 93-94% अब भी अनुदानों से आते हैं। यह निर्भरता पंचायतों के स्थानीय पहलों को कमजोर कर रही है। वे आत्मनिर्भर स्थानीय शासनके बजाय सरकार की योजनाओं को लागू करने वाली एजेंसी बन गए हैं। इसे बदलने का समय आ गया है, केवल टैक्स नियमों की समीक्षा ही नहीं की जानी चाहिए, बल्कि पंचायतों को उद्यमशील मानसिकता भी अपनानी चाहिए।

सुशील कुमार लोहानी
(भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय में अपर सचिव)

यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि वित्तीय नियंत्रण के बिना, ग्राम पंचायतें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजना नहीं बना सकतीं या प्राथमिकता तय नहीं कर सकतीं। एनआईपीएफपी की रिपोर्ट बताती है कि जहाँ संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क, या सामुदायिक संपत्ति के माध्यम से आर्थिक संभावनाएँ मौजूद हैं, वहां भी - नवाचार, डिजिटल प्रणाली और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी कार्य-प्रदर्शन को सीमित करती है। केरल, कर्नाटक और गोवा जैसे राज्यों का प्रति व्यक्ति ओएसआर अधिक है (क्रमशः ₹286, ₹148, और ₹1,635)। इनमें डिजिटल तरीके से टैक्स संग्रह और सामुदायिक भागीदारी भी है।

नाभिकीय ऊर्जा मिशन

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

विकासित भारत को साकार करने के लिए बड़े पैमाने पर नाभिकीय ऊर्जा का तेज़ी से इस्तेमाल ज़रूरी हो गया है। स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच के अलावा, नाभिकीय ऊर्जा लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा और जलवायु सुरक्षा का भी वादा करती है। परमाणु ऊर्जा विभाग की लगातार और आत्मनिर्भर बनने कोशिशों की वजह से, भारत एक आत्मनिर्भर, ज़िम्मेदार देश के तौर पर उभरा है, जिसके पास प्रगत नाभिकीय प्रौद्योगिकी है, भले ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने हम पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हों। देश अब नाभिकीय ऊर्जा मिशन के साल 2047 तक 100 GW बिजली बनाने की क्षमता तक पहुँचने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के मामले में तैयार है। हालाँकि यह बहुत महत्वाकांक्षी लग सकता है, लेकिन हमारे पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, पॉलिसी की पहल और काम, खासकर कानूनी कदम जो अभिप्रेत हैं, उनसे चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। स्वच्छ ऊर्जा हासिल करने और जलवायु खतरे से निपटने के अलावा, नाभिकीय ऊर्जा मिशन में अर्थव्यवस्था को काफ़ी बढ़ावा देने की क्षमता है क्योंकि पूरी वैल्यू चेन देश के अंदर होगी। इससे मटीरियल, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, ऑपरेशन और मेंटेनेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, सेफ्टी और आस-पड़ोस के लोगों से जुड़ाव जैसी सभी गतिविधियों में सभी स्तर पर नौकरियाँ पैदा होंगी। प्रशिक्षित और योग्य मानव संसाधन के मामले में भी चुनौतियां हैं। हालांकि हम इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन प्रोग्राम की निरंतरता पर उद्योग का भरोसा एक अनिवार्य शर्त होगी। आगे क्या चुनौतियां हैं? उनमें से सबसे ज़रूरी है समय लक्ष्य के हिसाब से बड़े पैमाने पर तेज़ी से परिनियोजन करना। सिर्फ़ दो दशकों में 90 GW से ज़्यादा या लगभग 200 रिएक्टर जोड़े जाने हैं। स्पष्ट है कि NPCIL, NTPC और BHAVINI के अलावा कई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियों की ज़रूरत है, जो फ्लीट मोड में रिएक्टर प्लांट के मानक डिज़ाइन वाली परियोजना शुरू करें। हालांकि हमें अपनी राष्ट्रीय नाभिकीय ऊर्जा नीति के आधार पर प्रौद्योगिकी के साथ प्रोग्राम को परिनियोजित करना चाहिए।

अनिल काकोडकर
(पूर्व सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं पूर्व अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग)

PHWR प्रौद्योगिकी स्पष्ट रूप से एक सिद्ध और किफायती प्रतिस्पर्धी स्वदेशी प्रौद्योगिकी है जो तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसलिए NPCIL को अपने प्रोग्राम को कार्यान्वित करते समय PHWR प्रौद्योगिकी में दूसरी प्राधिकरणों को रचनात्मक रूप अपने से जोड़ते हुए उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। दूसरी परिपक्व प्रौद्योगिकी को भी एक अतिरिक्त संभावना के तौर पर माना जा सकता है, बशर्ते वे किफायती और संरक्षा मानकों को पूरा करें।

निवेश का भी एक ज़रूरी मुद्दा है, जो अकेले नाभिकीय ऊर्जा उपयोगिता क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ के ऑर्डर का होगा। ईंधन चक्र अवसंरचना के लिए निवेश इसके अलावा होगा। इसलिए निजी क्षेत्र से वित्तपोषण बहुत ज़रूरी है। जबकि नाभिकीय क्षेत्र का आर्थिक पक्ष अच्छा है, दूसरी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के बराबर नीति सहयोग अनिवार्य होगा।

निर्धारित क्षमता के लिए नाभिकीय ईंधन हासिल करना अगली बड़ी चुनौती है। जबकि वैश्विक यूरेनियम स्रोत काफी हैं, नाभिकीय ऊर्जा विस्तार के कारण यूरेनियम की बढ़ती मांग और यूरेनियम आपूर्ति पर रुकावटों से अंतरिम आपूर्ति में कमी और मूल्य में वृद्धि होगी। नाभिकीय बाज़ार से जुड़ी जटिल भू-राजनीति को देखते हुए यह एक बड़ी ईंधन आपूर्ति सुरक्षा चुनौती बन सकती है। इसलिए अपने बड़े थोरियम भंडारों के साथ भारत को जल्द से जल्द थोरियम पर स्विच कर लेना चाहिए और ऊर्जा सुरक्षित बनना चाहिए। इसके लिए हमारे थोरियम आधारित नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम और उससे जुड़ी प्रौद्योगिकी के विकास में तेज़ी लाने की ज़रूरत है।

कमिश्नरेट पुलिस द्वारा 3 आरोपी गिरफ्तार, 25 किलो डोडा चूरा पोस्त तथा 350 ग्राम हेरोइन बरामद

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

जालंधर कमिश्नरेट पुलिस की सी.आई.ए. स्टाफ टीम ने दो अलग-अलग कार्रवाइयों के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके पास से व्यावसायिक मात्रा में 25 किलो डोडा चूरा पोस्त तथा 350 ग्राम हेरोइन बरामद करने में सफलता

हासिल की है। पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार की नशा विरोधी मुहिम के तहत यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। उन्होंने बताया कि डी.सी.पी. (इन्वेस्टिगेशन) मनप्रीत सिंह ढिल्लों, ए.डी.सी.पी. (इन्वेस्टिगेशन) जयंत पुरी तथा ए.सी.पी. (डी) अमरबीर सिंह की निगरानी के अधीन इंस्पेक्टर सुरिंदर कुमार इंचार्ज सी.आई.ए. स्टाफ जालंधर की अगुवाई में पुलिस टीम द्वारा यह सफल कार्रवाई की गई।

उन्होंने आगे बताया कि 17 दिसंबर 2025 को सी.आई.ए. स्टाफ की पुलिस टीम नई दाना मंडी, दुर्गा कॉलोनी जालंधर में मौजूद थी। इस दौरान दुर्गा कॉलोनी मोड़ के पास एक व्यक्ति को शक के आधार पर रोककर काबू किया गया, जिसकी पहचान नछत्तर सिंह पुत्र कुलवंत सिंह निवासी हवेलियां, थाना सराय अमानत खां, जिला तरनतारन के तौर पर हुई। तलाशी के दौरान उसके पास से 25 किलो डोडा चूरा पोस्त बरामद

हुआ। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ मुकदमा नंबर 150 दिनांक 17.12.2025 के तहत धारा 15/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना डिवीजन नंबर 2, जालंधर में दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि 18 दिसंबर 2025 को एक अन्य कार्रवाई के दौरान सी.आई.ए. स्टाफ की टीम ने फुल्लां वाली मार्किट के पास दो नौजवानों को काबू किया, जिनकी पहचान निशान सिंह पुत्र धर्मपाल तथा बिट्टू सिंह पुत्र दोना सिंह दोनों निवासी गांव अमृतपुर, थाना तलवंडी चौधरियां, जिला कपूरथला के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उनके पास से 350 ग्राम हेरोइन बरामद की गई।

इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा नंबर 151 दिनांक 18.12.2025 के तहत धारा 21-सी/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना डिवीजन नंबर 2, जालंधर में दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी इस समय पुलिस रिमांड पर हैं, जिनसे पूछताछ जारी है।

कमिश्नरेट पुलिस जालंधर द्वारा एक युवक सहित 50 ग्राम हेरोइन बरामद

जालंधर (जालंधर ब्रीज). जालंधर कमिश्नरेट पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पुलिस कमिश्नर धन्नप्रीत कौर के दिशा-निर्देशों के तहत मनप्रीत सिंह ढिल्लों डीसीपी/आईएनवी, जयनत पुरी एडीसीपी/आईएनवी और अमरबीर सिंह एसीपी/डी की निगरानी में, इंस्पेक्टर सरबजीत सिंह (इंचार्ज क्राइम ब्रांच) की अगुवाई में कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 50 ग्राम हेरोइन बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस कमिश्नर धन्नप्रीत कौर ने बताया कि दिनांक 17 दिसंबर को क्राइम ब्रांच की टीम वेरका मिल्क प्लांट चौक से सर्विस राउंड पर इंदिरा कॉलोनी की ओर जा रही थी। इस दौरान होटल डब्ल्यू ग्रैंड के पास एक युवक को शक के आधार पर रोककर तलाशी ली गई, जिसमें से 50 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रज्जत पुत्र लारैस, निवासी

नज़दीक सरकारी स्कूल, गांव दयालपुर, थाना सुबानपुर, जिला कपूरथला के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ केस नंबर 259 दिनांक 17.12.2025 धारा 21B/61/85 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत थाना डिवीजन नंबर-1, कमिश्नरेट जालंधर में मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पहले से भी थाना सुबानपुर, जिला कपूरथला में दो अन्य मुकदमे दर्ज हैं और आरोपी हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था।

नशा तस्कर महिला की अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का पीला पंजा

पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा करके की गई थी निर्माण, नशा तस्करी के 8 अलग-अलग मामलों का कर रही थी सामना, काली कमाई से बनाई संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई जारी: एसएसपी

• **जालंधर ब्रीज.** कपूरथला/सुभानपुर

पंजाब सरकार की नशा तस्करों के खिलाफ चल रही "युद्ध नशे के विरुद्ध" मुहिम के तहत सिविल और पुलिस प्रशासन द्वारा बीडीपीओ नडाला के आदेशों पर नशा तस्कर की अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। पिंड लखण खोले, थाना सुभानपुर के अधीन जगीर कौर उर्फ बिल्लो पत्नी किशन सिंह, निवासी लखण खोले द्वारा पंचायती जमीन पर किए कब्जे पर प्रशासन द्वारा पीला पंजा चलाया गया।

एसएसपी कपूरथला गौरव तूरा ने बताया कि बीडीपीओ नडाला द्वारा जारी आदेशों के अनुसार बताया गया था कि समाज विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेते हुए जगीर कौर उर्फ बिल्लो पिंड लखण खोले द्वारा पंचायती जमीन पर कब्जा करके घर बनाया हुआ है। बीडीपीओ के अनुसार जग्गीर कौर को बार-बार नोटिस जारी करके अवैध कब्जा खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने अवैध कब्जा नहीं छोड़ा, जिस कारण पुलिस की मदद मांगी गई थी। उन्होंने कहा कि जगीर कौर उर्फ बिल्लो के खिलाफ विभिन्न थानों में एनडीपीएस के 8 मामले दर्ज थे। इसमें एफआईआर नंबर 30, 127, 183, 85 और 239 के तहत थाना सुभानपुर तथा एफआईआर नंबर 33 के तहत थाना भोगपुर (जालंधर) में मामले दर्ज हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजाब सरकार के सख्त निर्देशों के तहत जिला पुलिस नशा तस्करी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है और किसी भी नशा तस्करी से जुड़े व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा तथा कानून अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि नशा तस्करी के खिलाफ यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी।

पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का नींव पत्थर रखा

6.5 लाख रुपये की लागत से पार्क के कार्य को किया जाएगा पूरा

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी, रक्षा सेवाएं कल्याण तथा बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने मॉडल हाउस के केपी नगर में 6.5 लाख रुपये की लागत से पार्क के सौंदर्यीकरण के कार्य का नींव पत्थर रखा । इस मौके पर उनके साथ मेयर नगर निगम वनीत धीर भी मौजूद थे। पार्क के सौंदर्यीकरण का नींव पत्थर रखने के बाद लोगों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि पार्क के सौंदर्यीकरण और इसके बुनियादी ढांचे में और सुधार होने से लोगों को पार्क में सुबह तथा शाम की सैर करने के

अलावा शारीरिक व्यायाम करने में और अधिक सुविधा मिलेगी।

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री, पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार द्वारा जालंधर शहर के सर्वांगीण विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में किए जा रहे विकास कार्यों के कारण इसे एक नई दृष्टि मिल रही है, जिससे शहरवासियों को साफ-सुथरा तथा प्रदूषण मुक्त वातावरण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा शहर में किए जाने वाले विकास कार्यों के लिए बड़े स्तर पर फंड जारी किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शहर को और अधिक खूबसूरत तथा बुनियादी ढांचे की दृष्टि से और मजबूत बनाने के लिए विकास कार्यों की शुरुआत की जाएगी और इसके लिए फंड की कोई कमी नहीं है।

इस मौके पर मेयर वनीत धीर ने कहा कि नगर निगम द्वारा शहर को सुंदर बनाने के लिए लगातार गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर की पार्कों तथा चौकों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है जो शहर को और भी अधिक खूबसूरत दृष्टि प्रदान कर रहा है। इस मौके पर क्षेत्र निवासियों ने पंजाब सरकार द्वारा शहर को बुनियादी ढांचे की दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई पहलकदमियों की भरपूर प्रशंसा की गई। उन्होंने कहा कि शहर का जो विकास उन्हें मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के समय देखने को मिल रहा है वह पहले कभी नहीं देखा गया।

सौर ऊर्जा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए बैंकों की अहम भूमिका : डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन

कहा- ग्राहकों को सोलर रूफटॉप से जुड़ी सब्सिडी, वित्तीय सहायता और तकनीकी पहलुओं की जानकारी दें

• **जालंधर ब्रीज.** होशियारपुर

डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन की अध्यक्षता में जिला प्रशासन की ओर से जिले के सभी बैंकों के क्लस्टर हेड्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक केंद्र व राज्य सरकार की गो सोलर पहल के तहत आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को सोलर रूफटॉप सिस्टम अपनाने के लिए प्रेरित करना है। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने बताया कि इससे पहले इस

परियोजना के तहत विभिन्न सरकारी विभागों को जोड़ा गया था, ताकि आम लोगों तक सौर ऊर्जा के लाभ पहुंचाए जा सकें। अब इस पहल को और प्रभावी बनाने के लिए बैंकों को भागीदार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैंकों का व्यापक ग्राहक आधार है और बैंक अपने ग्राहकों के माध्यम से सोलर रूफटॉप योजना की जानकारी घर-घर तक पहुंचा सकते हैं। आशिका जैन ने कहा कि यदि बैंक अपने ऋण, होम लोन, एमएसएमई और अन्य वित्तीय सेवाओं के साथ सोलर रूफटॉप सिस्टम को भी बढ़ावा दें, तो लोग आसानी से इस योजना को अपनाने के लिए आगे आएंगे। इससे न केवल बिजली बिल में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने बैंकों से अपील की कि वे अपने ग्राहकों को सोलर रूफटॉप से जुड़ी सब्सिडी, वित्तीय सहायता और तकनीकी पहलुओं की जानकारी दें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। डिप्टी कमिश्नर ने विश्वास जताया कि जिला प्रशासन और बैंकों के संयुक्त प्रयास से गो सोलर अभियान को नई गति मिलेगी और होशियारपुर जिला स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा की दिशा में एक मिसाल बनेगा।

इस मौके पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) निकास कुमार, सहायक कमिश्नर (सामान्य) ओएशी मंडल, सचिव रेडक्रॉस सोसायटी मंगेश सूद, संयुक्त सचिव आदित्य राणा के अलावा विभिन्न बैंकों के अधिकारी भी मौजूद थे।

'आप' की दबाव की राजनीति के बावजूद कांग्रेस की जीत : बाजवा

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि कादियां विधानसभा क्षेत्र में हुए ज़िला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों के नतीजे कांग्रेस के लिए एक नैतिक और राजनीतिक जीत हैं, जो आप सरकार के लगातार दबाव और प्रशासन के खुले दुरुपयोग के बावजूद हासिल की गई है। बाजवा ने कहा कि

ज़िला परिषद चुनावों में कांग्रेस ने 3 में से 2 सीटें — काहनूवां और तुगलवाल — जीतकर लोकतांत्रिक और जनहितैषी राजनीति में जनता के गहरे विश्वास को दर्शाया है।

ब्लॉक समिति के नतीजों का विवरण देते हुए बाजवा ने कहा कि काहनूवां ब्लॉक (15 सीटें): कांग्रेस - 10, आप - 5, अकाली दल - 0। धारीवाल ब्लॉक (17 सीटें): 9 सीटों पर नामांकन मनमाने ढंग से रद्द कर दिए गए, जिसके कारण केवल 8 सीटों पर ही चुनाव हो सका जिसमें से कांग्रेस - 5, आप - 2, अकाली दल - 1 सीट जीतो। बाजवा ने कहा, "ये नतीजे साफ तौर पर साबित करते हैं कि भारी राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक हस्तक्षेप और हेरफेर के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवारों ने जनता का विश्वास हासिल किया है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि धारीवाल ब्लॉक में चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और निष्कलंक तरीके से कराए गए होते, तो नतीजे कांग्रेस के पक्ष में कहीं अधिक निर्णायक होते। "9 नामांकनों का मनमाना रद्द किया जाना आप सरकार के जनता के फैसले से डर को उजागर करता है," उन्होंने कहा।

बाजवा ने कहा कि कादियां की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि दबाव की राजनीति से लोकतंत्र को कुचला नहीं जा सकता। "यह जनादेश डराने-धमकाने, सत्ता के दुरुपयोग और पुलिस-प्रबंधित राजनीति की करारी नकार है," उन्होंने कहा। भविष्य को लेकर विश्वास जताते हुए बाजवा ने कहा, "यदि कांग्रेस इतनी समझौता-ग्रस्त चुनावी परिस्थितियों में भी ऐसे नतीजे दे सकती है, तो यह स्पष्ट है कि पंजाब की जनता बदलाव के लिए तैयार है। 2027 में जनता के आशीर्वाद से पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी।"

त्रैमासिक पेंशन अदालत का आयोजन

संगरूर (जालंधर ब्रीज). संगरूर में डॉ. मनदीप सिंह, संयुक्त नियंत्रक, नियंत्रक संचार लेखा, पंजाब, चंडीगढ़ के कार्यालय की अध्यक्षता में त्रैमासिक पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। पेंशन अदालत के दौरान पेंशनभोगियों से कुल पांच पेंशन संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से चार शिकायतों का मौके पर ही संबंधित अधिकारियों के साथ समुचित जांच एवं संवाद के उपरांत समाधान कर दिया गया। एक शिकायत BSNL से संबंधित थी, जिसे आवश्यक कार्रवाई हेतु बीएसएनएल प्राधिकरण को अग्रेषित किया गया। शिकायत निवारण के साथ-साथ पेंशनभोगियों के हित में विशेष जागरूकता सत्रों का भी आयोजन किया गया। इन सत्रों में स्वास्थ्य एवं कल्याण, योग, साइबर अपराध से सुरक्षा तथा निवेश जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्रदान की गई, जिससे पेंशनभोगियों में स्वस्थ, सुरक्षित एवं जागरूक जीवनशैली को बढ़ावा मिल सके। पर्यावरण संरक्षण में योगदान देते हुए, कार्यक्रम के दौरान कार्यालय द्वारा पेंशनभोगियों एवं उनके परिवारजनों को पौधों का वितरण भी किया गया। पेंशन अदालत में बीएसएनएल तथा सीसीए, पंजाब कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने पेंशनभोगियों की समस्याओं के समाधान में सक्रिय सहभागिता निभाई। यह पेंशन अदालत पेंशनभोगियों एवं अधिकारियों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक प्रभावी मंच सिद्ध हुई, जिससे शिकायतों का त्वरित समाधान तथा उपयोगी जानकारी का प्रभावी प्रसार सुनिश्चित हुआ।

आर्मी अग्निवीर के जनवरी बैच के लिए सी-पाइट कैंप में ट्रेनिंग शुरू

एसएससी की नई भर्ती के लिए भी ट्रेनिंग जारी

• **जालंधर ब्रीज.** कपूरथला

सी-पाइट थेह कांजला कपूरथला के अधिकारी कैप्टन अजीत सिंह ने बताया कि आर्मी अग्निवीर के जनवरी बैच की भर्ती के लिए शारीरिक और लिखित पेपर की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है तथा कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, अमृतसर और गुरदासपुर के इच्छुक उम्मीदवार कैंप में आकर पंजाब सरकार द्वारा मुहैया करवाई जा रही मुफ्त ट्रेनिंग का लाभ ले सकते है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा एस.एस.सी. की नई भर्ती के लिए भी कैंप में ट्रेनिंग जारी है।

उन्होंने कहा कि जो भी इच्छुक उम्मीदवार इन पेपरों की तैयारी करना चाहते हैं, वे सी-पाइट कैंप थेह कांजला में जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, दसवीं या बारहवीं क्लास का सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट और दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर कैंप में रिपोर्ट कर सकते है। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को मुफ्त रहने और खाने की सुविधा भी मुहैया करवाई जाती है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए इन मोबाइल नंबरों 69002-00733 और 83601-63527 पर संपर्क किया जा सकता है।

आईसीसी रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती की बढ़त मजबूत

भारतीय गेंदबाज ने 818 अंकों का अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया

स्पोर्ट्स डेस्क. भारतीय मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने आईसीसी पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज रैंकिंग में शीर्ष पर अपनी बढ़त और मजबूत कर ली है और अपने करियर की नई उच्चतम रेटिंग हासिल कर ली है। आईसीसी की वेबसाइट के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही पांच मैचों की घरेलू टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में लगातार तीसरी बार दो विकेट लेने के बाद भारतीय गेंदबाज ने 818 अंकों का अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया है।

दाएं हाथ के लेग स्पिनर ने श्रृंखला के पहले तीन मैचों में छह विकेट लिए हैं, जिनमें धर्मशाला में खेले गए तीसरे भारत-दक्षिण अफ्रीका टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में चार ओवरों में 2/11 के उनके प्रभावशाली आंकड़े शामिल हैं, जिन्होंने भारत की सात विकेट की शानदार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 818 रेटिंग अंकों के साथ, चक्रवर्ती अब दूसरे स्थान पर मौजूद न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी (699) से 119 अंकों की बड़ी बढ़त पर हैं। 34 वर्षीय चक्रवर्ती टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में सर्वकालिक शीर्ष 10 में भी शामिल हो गए हैं।

यह खबर भारत के लिए समय पर आई है, क्योंकि वेस्ट इंडीज में पिछले साल जीती गई आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की उपाधि का बचाव करने में दो महीने से भी कम समय बचा है। चक्रवर्ती से उम्मीद की जा रही है कि वे लगातार दूसरी बार खिताब जीतने की दौड़ में अहम भूमिका निभाएंगे। भारत के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के तीसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में चार पायदान ऊपर चढ़कर 16वां स्थान हासिल कर लिया है। वहीं, दक्षिण अफ्रीका की रैंकिंग में भी कई सुधार देखने को मिले हैं। मार्को जानसेन 14 पायदान ऊपर चढ़कर 25वें स्थान पर, लुंगी एनगिडी 11 पायदान ऊपर चढ़कर 44वें स्थान पर और ओटनेल बार्टमैन शीर्ष 100 से बाहर से छलांग लगाकर 68वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

अब आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारत के दो बल्लेबाज शीर्ष पांच में शामिल हैं। तिलक वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन शानदार पारियों के बाद दो पायदान ऊपर चढ़कर चौथा स्थान हासिल कर लिया है।

फोटो-बीसीसीआई

भुल्लर की अध्यक्षता में हुई पंजाब स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की 16वीं बैठक

5 ट्रामा केयर सेंटरों के आधुनिकीकरण के लिए 66 लाख रुपये के फंड जारी करने का निर्णय

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की 16वीं बैठक पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक के दौरान काउंसिल द्वारा 5 ट्रामा केयर सेंटरों के आधुनिकीकरण के लिए 66 लाख रुपये के फंड जारी करने का फैसला किया गया। इस मौके पर ई-डार प्रोजेक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 415 स्मार्ट फोन पुलिस विभाग के आईओज़ को देने का फैसला भी लिया गया। इसके अलावा 35 ए.एल.एस. एम्बुलेंसों के लिए 14 करोड़ रुपये 31 मार्च, 2026 तक जारी करने का फैसला भी काउंसिल द्वारा लिया गया।

यहां पंजाब भवन चंडीगढ़ में हुई इस बैठक में विस्तार से ई-डार प्रोजेक्ट संबंधी, ब्लैक स्पॉट की रेक्टीफिकेशन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की

गई। इस मौके पर पंजाब सरकार और भारत सरकार की स्कीमों गुड स्मार्टियन को अवार्ड देने संबंधी, हिट एंड रन के प्रभावित व्यक्तियों को लाभ देने संबंधी, रोड एक्सीडेंट के प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त इलाज, फरिश्ते स्कीम पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, इंटरसेप्टर्स, रिकवरी वैन, एल्कोमीटर जल्द से जल्द खरीदने के निर्देश दिए गए ताकि इन्फोर्समेंट के काम में सुधार लाया जा सके।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at DB Corp Ltd, J7 NEAR BUS STAND SUBHANPUR (HAMIRA), KAPURTHALA, PUNJAB - 144808, and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.